हरिशचंद्र हेगड़े

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

18 दिसंबर, 2003

[न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा और न्यायाधिपति अरुण कुमार]

कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1978:

धारा 4 और 5- अनुदान प्राप्तकर्ता को भूमि की बहाली- भूमि में किए गए सुधारों के मूल्य के लिए हस्तांतरणकर्ता का दावा- सरकारी अनुदान प्राप्तकर्ता-1962 में भूमि का हस्तांतरण- अनुदान की शर्तों के उल्लंघन में किए गए हस्तांतरण को अमान्य घोषित करने वाला अधिनियम- मूल अनुदान प्राप्तकर्ता को भूमि बहाल- हस्तांतरणकर्ता यह दावा करते हुए कि आदेश धारा 5 के तहत द्वारा पारित किया गया था। संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रावधान निर्धारित धारा 51 के अनुसार सुधारों के मूल्य का दावा करने के उसके अधिकार के अधीन होगा - माना जाता है कि अधिनियम की धारा 5 में निहित परिणाम धारा 4 के तहत आदेश पारित होने की स्थिति में स्वचालित रूप से लागू होते हैं- धारा 4 जिसमें एक गैर-अस्थिर खंड शामिल है, किसी भी समझौते या किसी अन्य

कानून में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद लागू होगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम का बल-धारा 51 अंतर-जीवित हस्तांतरण पर लागू होता है - यह कानून के संचालन द्वारा किए गए हस्तांतरण पर लागू नहीं होता है - यदि भूमि को वापस बहाल करने के लिए न्यायिक आदेश पारित किया जाता है।

क़ानून के तात्पर्य और उद्देश्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति का सदस्य, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे मामले में लागू नहीं किया जा सकता है

तथ्यों पर, मामला विशेष क़ानून यानी अधिनियम द्वारा शासित होता है, जबकि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है- जब तक कि अधिनियम में कोई प्रावधान मौजूद न हो, तब तक इसके तहत पारित आदेश को एक अन्य कानून हस्तांतरण की धारा 51 के संदर्भ में पूरक या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।- संपत्ति अधिनियम का संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882-धारा 51 के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं माना जा सकता है-

मंचेगौड़ा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य [1984] 3 एस. सी. सी. 301, पर भरोसा किया।

अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति और अन्य जे टी (2003) 9 एस. सी 201 और कृष्णप्पा एस. वी. और अन्य बनाम कर्नाटक

राज्य और अन्य आई. एल. आर. (1982) 2 कर, 1310, संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5385/1997

कर्नाटक उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. ए. संख्या 1045/1992 में दिनांक 16.2.96 के निर्णय और आदेश से।

गिरीश अनांठमुर्थी और पी पी सिंह अपीलार्थी के लिए

कविन गुलरी और संजय आर हेगड़े प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 1992 की रिट अपील संख्या 1045 में पारित दिनांक 16.2.1996 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न इस अपील में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न आता है, वह यह है कि क्या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 51 कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम, 1978 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 4 और 5 के तहत आने वाले मामलों में लागू होती है।

1.5.1961 पर या उसके आसपास, सर्वेक्षण संख्या 134/110 में दो एकड़ भूमि कर्नाटक सरकार द्वारा एक श्रीमती गंगम्मा के पक्ष में दी गई थी। । अपीलार्थी ने 13.9.1962 पर मूल्यवान विचार के लिए एक पंजीकृत

बिक्री विलेख के माध्यम से उससे उक्त भूमि खरीदी और कथित तौर पर उसके सुधार के लिए बहुत पैसा निवेश किया। यह अधिनियम 1.1.1979 से लागू हुआ।

अधिनियम की धारा 4 के कारण किए गए सभी हस्तांतरण अनुदान की शर्तों के उल्लंघन को अमान्य घोषित कर दिया गया और ऐसी सभी भूमि को फिर से शुरू कर दिया गया और अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में मूल अनुदान प्राप्तकर्ता को बहाल कर दिया गया। 11.9.1986 को या उसके आसपास मूल अनुदानकर्ता ने अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन किया, जिसके अनुसरण में अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। सहायक आयुक्त द्वारा 29.5.1987 पर मूल अनुदानकर्ता के पक्ष में भूमि की बहाली का आदेश दिया गया था। अपीलार्थी ने इसके विरुद्ध उपायुक्त के समक्ष एक अपील दायर की जिसे 25.3.1989 पर भी खारिज कर दिया गया।

इसके बाद अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की जो थी इस घोषणा के लिए 1990 की रिट याचिका संख्या 23216 के रूप में चिह्नित किया गया है कि भूमि की बहाली के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत सहायक आयुक्त द्वारा पारित कोई भी आदेश धारा 51 के तहत निर्धारित सुधारों के मूल्य का दावा करने के अंतरिती के अधिकार के अधीन होगा। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के उक्त रिट याचिका विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट अपील भी दिनांक 16.2.1996 के एक आदेश के कारण खारिज कर दी गई थी।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता ने 13.9.1962 को प्रश्नगत भूमि खरीदी थी, वह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 51 के लाभ का हकदार है।

अधिनियम की धारा 4 और 5 निम्नानुसार हैः

"धारा 4 दी गई भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध - (1) किसी भी कानून, समझौते, अनुबंध या साधन में किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में दी गई भूमि का कोई भी हस्तांतरण, ऐसी भूमि के अनुदान की शर्तों या ऐसे अनुदान के लिए प्रदान करने वाले कानून या उप-धारा के उल्लंघन में होता है। (2) अमान्य और शून्य होगा और कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं होगा ऐसी भूमि में ऐसे हस्तांतरण द्वारा संप्रेषित किया जाएगा या कभी संप्रेषित किया गया समझा जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी स्वीकृत भूमि का हस्तांतरण या अधिग्रहण करना।

(3) उपधारा (1) और (2) के प्रावधान किसी सिविल कोर्ट के डिक्री या आदेश या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी पुरस्कार या आदेश के निष्पादन में किसी भी भूमि की बिक्री पर भी लागू होंगे।

धारा 5. दी गई भूमि का पुनःग्रहण या प्रत्यास्थापन। :-(1) जहां, किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन पर या किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में दी गई जानकारी पर या स्वतः संज्ञान से, और ऐसी जांच के बाद जो वह आवश्यक समझे, सहायक आयुक्त संतुष्ट है कि किसी भी दी गई भूमि का हस्तांतरण शून्य और शून्य है धारा 4 की उपधारा (1) के तहत, वह कर सकता है।

(ए) आदेश द्वारा ऐसी भूमि पर कब्जे वाले सभी व्यक्तियों को बेदखल करने के बाद उस तरीके से कब्जा कर लें जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है: बशर्ते कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के अलावा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा;

(बी) ऐसी भूमि को मूल अनुदान प्राप्तकर्ता या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को वापस कर देगा। जहां ऐसे अनुदान प्राप्तकर्ता या कानूनी उत्तराधिकारी को भूमि वापस करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, ऐसी भूमि को सभी बाधाओं से मुक्त सरकार में निहित माना जाएगा। सरकार भूमि अनुदान से संबंधित नियमों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ऐसी भूमि दे सकती है।

(2) उप-धारा (1) के तहत पारित कोई भी आदेश अंतिम होगा और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा और सहायक आयुक्त द्वारा की गई या उठाए जाने वाली किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी भी अदालत द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई भी दी गई भूमि मूल अनुदान प्राप्तकर्ता या उसके कानूनी उत्तराधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति ने हस्तांतरण द्वारा भूमि अर्जित की है जो धारा 4 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत अमान्य है।

उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में कहा कि कृष्णप्पा एस. वी. और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य आई. एल. आर. (1982) 2 कर, 1310 में उच्च न्यायालय द्वारा वैधता अधिनियम को बरकरार रखा गया था।

"इस प्रकार, यदि दी गई भूमि के किसी विदेशी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 5 के तहत सहायक आयुक्त द्वारा बेदखल कर दिया जाता है, तो विदेशी व्यक्ति ऐसी भूमि पर खड़ी फसल और उसके द्वारा लगाए गए फिक्स्चर को हटा सकता है। वह खरीद के पैसे की वापसी के लिए अपने विदेशी पर मुकदमा कर सकता है। वह मूल अनुदान प्राप्तकर्ता

या उसके उत्तराधिकारियों से, जिन्हें ऐसी भूमि बहाल की गई है, उस भूमि में उनके द्वारा किए गए सुधारों के मूल्य का दावा भी कर सकता है। खरीद धन की ऐसी वापसी पाने का अधिकार और ऐसे सुधारों के मूल्य का दावा करने का अधिकार , अधिनियम की धारा 5 के तहत दी गई भूमि से बेदखल होने पर पट्टेदार को होने वाली कठिनाई कुछ हद तक कम हो जाएगी।"

यह न्यायालय मंचेगौड़ा और अन्य कर्नाटक राज्य और अन्य [1984] 3 एस. सी. सी. 301 ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधिकारों पर विचार करते हुए, जिसमें हस्तांतरणकर्ता के अधिकार, मुआवजे का भुगतान आदि शामिल हैं, यह अभिनिर्धारित किया कि इस तरह के अनुदान मुआवजे का दावा करने और तब तक हस्तांतरणकर्ताओं को कब्जे में बनाए रखने का प्रश्न प्रदान करते हैं। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कोई लेन-देन सार्वजनिक नीति के खिलाफ होता है जैसे की कमजोर वर्गों से संबंधित अनुदान प्राप्तकर्ताओं द्वारा दूसरों को भूमि के हस्तांतरण के मामले में, ऐसा हस्तांतरण अमान्य हो जाता है। इन निष्कर्षों पर रिट याचिका खारिज कर दी गई।

अधिनियमः

इस अधिनियम को संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था, जिसमें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भी

शामिल थे। जैसे समाज के कमजोर वर्ग और विशेष रूप से एससी और एसटी श्रेणियों से संबंधित लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। अधिनियम के प्रावधानों के कारण राज्य ने यदि यह पाया जाता है कि भूमि का कोई हस्तांतरण अनुदान की शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया गया है तो भूमि को फिर से शुरू करने और अनुदान प्राप्तकर्ताओं को उसे बहाल करने का अधिकार है। कार्यवाही को फिर से शुरू करने के इस तरह के आदेश को अनावश्यक देरी या कार्यवाही को आगे बढ़ाने से बचने के लिए पारित किया जाना आवश्यक है।

मंचेगौड़ा (ऊपर) में यह आयोजित किया गया थाः

"दी गई भूमि के हस्तांतरणकर्ताओं को कानूनी स्थिति की पूरी जानकारी है कि अनुदान की शर्तों या ऐसे अनुदान को नियंत्रित करने वाले किसी भी कानून, नियम या विनियमन के उल्लंघन में उनके पक्ष में किए गए हस्तांतरण कानून में पराजित होने के लिए उत्तरदायी हैं, ऐसा नहीं हो सकता है और न ही हो सकता है। कानून या समानता, एक वास्तविक या वास्तविक शिकायत कि इस तरह से हस्तांतरित की गई ऐसी भूमि में उनका अक्षम्य अधिकार, वास्तव में, पराजित किया जा रहा है और उन्हें ऐसी भूमि से बेदखल किया जा रहा है जहाँ से वे कानून की प्रक्रिया द्वारा बेदखल किए जाने के लिए उत्तरदायी थे।"

संपत्ति के हस्तांतरण (1882 का अधिनियम संख्या 4) पक्षों को अधिनियम द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून में संशोधन करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।अधिनियम की धारा 2 (डी) इस प्रकार हैः

2. अधिनियमों का निरसन-कुछ अधिनियमों, घटनाओं, अधिकारों, देनदारियों आदि की बचत-उन क्षेत्रों में जहां यह अधिनियम कुछ समय के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों का विस्तार करता है।यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों को उसमें उल्लिखित सीमा तक निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें शामिल किसी भी चीज़ को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा -

XXX XXX XXX

(घ) इस अधिनियम की धारा 57 और अध्याय iv द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, कानून के संचालन द्वारा या उसके सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय की डिक्री या आदेश निष्पादन में कोई हस्तांतरण; और इस अधिनियम के दूसरे अध्याय में कुछ भी नहीं माना जाएगा यह मुस्लिम विधि के किसी भी नियम को प्रभावित करता है।

उक्त अधिनियम की धारा 51 इस प्रकार हैः

"51 दोषपूर्ण स्वामित्व के तहत वास्तविक धारकों द्वारा किए गए सुधार - जब अचल संपत्ति का हस्तांतरणकर्ता संपत्ति पर कोई सुधार करता है, सद्भावना में विश्वास करता है कि वह पूरी तरह से इसका हकदार है, और बाद में उसे बेहतर शीर्षक वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा बेदखल कर दिया जाता है, अंतरिती को इसका अधिकार है बेदखली का कारण बनने वाले व्यक्ति से या तो सुधार के मूल्य का अनुमान लगाने और अंतरिती को भुगतान या सुरक्षित करने की अपेक्षा करें, या ऐसे सुधार के मूल्य की परवाह किए बिना, संपत्ति में ब्याज को उसके तत्कालीन बाजार मूल्य पर अंतरिती को बेचने की अपेक्षा करें।

इसके संबंध में भुगतान की जाने वाली या सुरक्षित की जाने वाली राशि बेदखली के समय सुधार उसका अनुमानित मूल्य होगा। जब, उपरोक्त परिस्थितियों में, अंतरिती ने संपत्ति पर ऐसी फसलें लगाई या बोई हैं जो वहां से बेदखल होने पर उग रही थीं, तो वह ऐसी फसलों का हकदार है और स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का हकदार है। और उन्हें इकट्ठा करने और बाहर ले जाने के लिए।"

अधिनियम की धारा 4 के तहत पारित एक आदेश के अनुसार, उसमें निर्दिष्ट अवैधताओं का पता चलने पर भूमि को बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। अधिनियम की धारा 5 में निहित परिणाम अधिनियम की धारा 4 के तहत एक आदेश पारित होने की स्थिति में स्वचालित रूप से

लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 4 में एक गैर-बाध्यकारी खंड है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान किसी भी समझौते या किसी अन्य अधिनियम में निहित कुछ भी होने के बावजूद लागू होगा। यह अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जबकि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम एक सामान्य अधिनियम है और इस मामले को देखते हुए भी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 51 का कोई उपयोग नहीं होगा और धारा 5 में निहित परिणाम प्रबल होंगे।

मानचेगौड़ा (ऊपर) में न्यायालय के दायरे की व्याख्या करते हुए अधिनियम की धारा 4 और 5 ने अभिनिर्धारित कियाः

"अधिनियम के अधिनियमन के साथ, प्रदत्त भूमि में हस्तांतरणकर्ता का अमान्य अधिकार या अधिकार शून्य हो जाता है और हस्तांतरणकर्ता के पास स्वीकृत भूमि में कोई अधिकार या संपत्ति नहीं रह जाती है। दी गई भूमि के हस्तांतरणकर्ताओं से जिन भूमि की वसूली करने की मांग की जाती है, वे ऐसी भूमि हैं जिनमें हस्तांतरणकर्ताओं का कोई हित या संपत्ति नहीं है। अधिनियम की धारा 4 और 5 में निहित प्रावधानों का प्रभाव यह है कि दी गई भूमि में हस्तांतरणकर्ताओं का अधिकार या हित विफल हो जाता है और अमान्य लेन-देन अमान्य हो जाता है। हम पहले यह मान चुके हैं कि हस्तांतरण पर प्रतिबंध की शर्त का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत भूमि के हस्तांतरण को अमान्य घोषित करना विधानमंडल के लिए

स्पष्ट रूप से खुला है। जैसे ही इस तरह के हस्तांतरण को अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर अमान्य कर दिया जाता है, हस्तांतरणकर्ता को इस तरह से हस्तांतरित की गई भूमि में कोई अधिकार नहीं होता है, और कब्जा करने की मांग की जाती है।ऐसी भूमि की पुनर्प्राप्ति जिसमें हस्तांतरणकर्ताओं ने अपना अधिकार और हित खो दिया है।"

फिर भी हाल ही में अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति और अन्य जे. टी.(2003) 9 एस. सी. 201 यह न्यायालय मंचेगवाडा (उपर्युक्त) के बाद और बड़ी संख्या में अन्य वाद आयोजित किए गएः

"आदिवासी क्षेत्रों की अपनी समस्याएं हैं। आदिवासी ऐतिहासिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग हैं। उन्हें कानूनों की सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि वे भोले-भाले हैं और बेईमान लोगों की रणनीति में फंस जाते हैं, और अपनी मासूमियत, गरीबी के कारण शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं और सदियों से चला आ रहा पिछड़ापन। भारत का संविधान और उसके तहत बनाए गए संविधान में जहां भी जरूरत हो, आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों को अलग-अलग माना जाता है। आदिवासियों को बसाने की जरूरत है, कानून की सुरक्षात्मक शाखा द्वारा उनकी देखभाल करने की जरूरत है, और उन्हें बेईमान व्यवस्था में फंसने से बचाया जाना चाहिए ताकि वे समृद्ध हो सकें और एक विकासवादी प्रक्रिया द्वारा समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। प्रक्रिया धीमी होगी, फिर भी इसे शुरू करना

होगा और आगे बढ़ाना होगा। 1950 अधिनियम और 1956 विनियमों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य यह देखना है कि एक आदिवासी जनजाति का सदस्य अनिश्चित काल तक उस संपत्ति का मालिक बना रहे जिसे वह अर्जित करता है और कानून द्वारा ज्ञात प्रत्येक प्रक्रिया जिसके द्वारा अचल संपत्ति में स्वामित्व एक व्यक्ति में समाप्त हो जाता है। किसी अन्य व्यक्ति में निहित होने का अधिकार, आदिवासियों के संबंध में अपने संचालन में इतना सीमित रहना चाहिए कि एक आदिवासी की अचल संपत्ति दूसरे आदिवासी में निहित हो सके, लेकिन किसी आदिवासी में निहित अचल संपत्ति का स्वामित्व किसी गैर-व्यक्ति में निहित नहीं होना चाहिए। आदिवासी. इसका उद्देश्य यह देखना और सुनिश्चित करना है कि गैर-आदिवासी संपत्ति अर्जित करके और आदिवासियों के निवास स्थान में जड़ें विकसित करके आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में सफल न हों।"

इस न्यायालय ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति 'स्थानांतरण' को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 51 अंतर-जीवन स्थानांतरण पर लागू होती है। यह, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, कानून के संचालन द्वारा किए गए हस्तांतरण पर लागू नहीं होता है। यदि कानून के तात्पर्य और उद्देश्य के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भूमि वापस करने का न्यायिक आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसे मामले में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए

जा सकते हैं। यह मामला एक विशेष कद द्वारा शासित होता है। जब तक उसमें कोई प्रावधान मौजूद नहीं है, तब तक उसके तहत पारित आदेश को किसी अन्य क़ानून के संदर्भ में प्रतिस्थापित या पूरक नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, हमारी राय है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 51 को तत्काल मामले में लागू नहीं माना जा सकता है। इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

आर. पी.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।